क्षम्य नहीं है। उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें तत्काल हटा देना चाहिए। महोदय, सदन से मेरी इतनी ही मांग है। धन्यवाद।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान): महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

Inappropriate air fare being charged on Delhi-Dharmashala sector

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ। महोदय, दिल्ली से धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) जाने और आने के लिए केवल किंगफिशर एयरलाएंस अपनी सेवा प्रदान करती है। प्रतिदिन एक फ्लाइट दिल्ली से धर्मशाला जाती है और वही फ्लाइट धर्मशाला से दिल्ली आती है। महोदय, सभी जानते हैं कि धर्मशाला एक पर्यटक गंतव्य है और हिमाचल के लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटक भी इसी एयरलाइंस की सेवा प्राप्त करते हैं। दिन में केवल एक ही फ्लाइट होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि उसमें कई-कई दिनों तक टिकट नहीं मिलती है और लोगों को टिकट के लिए कईकई दिनों तक वेटिंग में रहना पड़ता है। धर्मशाला के लिए एक फ्लाइट होने के कारण यह एयरलाइंस मनमाना किराया वसूल करती है, कई बार इसका किराया आठ हजार और नौ हजार रुपए तक पहुंच जाता है। मुंबई, बेंगलुरु, आदि अन्य स्थानों की तुलना में धर्मशाला का किराया बहुत अधिक होता है। दिल्ली-धर्मशाला दिल्ली सेक्टर पर किंगफिशर रेड की मोनोपोली बनी हुई है। मेरी सरकार से अनुरोध है कि एक एयरलाइंस की मोनोपोली और यात्रियों की अधिकता को देखते हुए सरकार धर्मशाला के लिए दूसरी एयरलाइंस को भी जल्दी से जल्दी introduce करे, ताकि यात्रियों से उचित किराया ही वसूला जा सके और यात्रियों को कई-कई दिनों की वेटिंग से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद।

Denial of rice allocation to Kerala for festival season

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I would like to draw the attention of the House to the step-motherly approach of the Central Government to the State of Kerala and the attack of the Central Government to dismantle the Public Distribution System. The Government of Kerala has submitted a memorandum for the allocation of rice under the special quota for Onam festival season. As all of us are aware, Onam is a national festival for Malayalees and the State Government has taken steps to control the price during the festival season. But the approach of the Central Government is totally negative. The Government of India denied the additional allocation beyond the present level of APL allocations. The letter from the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution stated that additional allocation beyond the present level of APL allocation to the State can be made at MSP based issue price of Rs. 10,800 per tonne for wheat and at applicable economic cost for rice. Hence the request for additional allocation of rice and wheat to Kerala on account of Onam festival requirement can be made only at the above price and not at the APL price. This is the letter from the Central Government. Then they can purchase it from FCI godowns at the economic cost of rice, which means Rs. 17.80 per kilogram

as compared to Rs. 8.90 per kilogram for APL. This would create a serious problem in Kerala. Kerala is the State where statutory rationing system was introduced with the consent of the Central Government in 1967 but the Centre has tried continuously to limit this system. Up to 2006, the allocation of rice to the APL cardholders is 1,13,420 tonnes, which has now been reduced to 17,056 tonnes only. The reduction is to the tune of 96,364 tonnes. This anti people move has been questioned by the State Government. The Chief Minister, the Ministers, and the MLAs were compelled to conduct a march to Parliament here. After the formation of the new Ministry, the Minister of State for Agriculture, Prof. K.V. Thomas, gave an assurance for reestablishing the rice quota but it remained only on paper. Now, the Government has courage to deny rice for Onam season. I urge the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to reconsider this decision and allocate sufficient rice at APL price to Kerala during Onam season. *...(Interruptions)...*

SOME HON. MEMBERS: Sir, we associate ourselves with the issue raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you just associate yourselves. *...(Interruptions)...* There is no rider in association. *...(Interruptions)...*

Naxal attack in Orissa

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): महोदय, उड़ीसा में कल शाम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में Keonjhar जिला, जो खान में भरपूर है, में दैतारी थाना के अन्तर्गत ब्राह्मणीपाल बीट हाउस है, वहां के एक असिस्टेंट सबइंस्पेक्टर, जो कि बीट हाउस में प्रभारी अधिकारी हैं, और उनके सहयोगी एक कांस्टेबिल दोनों को गोली से मार कर उनका गला काट दिया गया। जो ए.एस.आई. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार हुआ उनका नाम मुरलीधर बस्तिया है। जिस बेरहमी से उनकी हत्या की गई, उसके बारे में मैं आपके सामने यह जिक्र कर रहा हूं। इसे उग्रवाद ही कहा जाएगा, उसको अति वामवाद या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहना भी मेरे विचार से ठीक नहीं है। आपको पता है कि उड़ीसा में हर दिन इस प्रकार की घटना घटती हैं। अभी दस-बारह दिन पहले सुन्दरगढ़ जिला के कोइड़ा थाना के एक पुलिस इंस्पेक्टर अजित वर्धन को भी ऐसे ही बेरहमी से मारा गया। वह साक्ष्य देने के लिए राउरकेला गए थे। अजित वर्धन की बहादुरी और साहस का जिक्र करना मेरे लिए उचित होगा। वे जब वापिस आ रहे थे तो रात को 50 लोगों ने उनको घेर लिया, अजित वर्धन के साथ अन्य चार साधारण नागरिक भी थे। जिन 50 लोगों ने इन सब को घेर लिया तो उनको अजित वर्धन ने बताया कि इनमें से मैं ही अकेला पुलिसकर्मी हूं और बाकी अन्य चार लोग तो साधारण नागरिक हैं। तो उन साधारण चार नागरिकों को छोड़ दिया गया और अजित वर्धन को ले जाकर मार दिया गया। राज्य की सरकार जो कि सो रही है, जबकि उसको सत्ता में आए लगभग सौ दिन पूरे हो रहे हैं, अब तीसरी बार जीतने के बाद, वह अजित की हत्या के चालिस घंटे बाद मौके पर पहुंचती है। इस प्रकार से पुलिसकर्मियों को टारगेट बनाया जा रहा है। महोदय, आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में 36 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। अगर हम इसको अति वामवादी उग्रवाद कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि कभी भी चीन के माओ ने यह नहीं बताया था कि बेरहमी से आम नागरिकों और पुलिसकर्मियों को मारा जाए। इसलिए अगर इसको कोई माओवाद कहता है तो इस मामले को भी चीन के साथ उठाया जाना चाहिए। महोदय, मेरा इतना कहना है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, लालगढ़ और रामगढ़ क्यों न हो, हर स्थान पर यह जो आतंकवाद, उग्रवाद हो रहा है, इसके प्रति केन्द्र तुरन्त ध्यान दे, और विशेषकर के उड़ीसा में जहां पर कानून और व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है।